

“ NEP 2020: संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ ”

केशव मिश्रा

(सहायक आचार्य)

राजस्थान शिक्षक प्रशिक्षण विद्यापीठ, शाहपुरा बाग, जयपुर

सारांश -

भारतीय शैक्षिक ढाँचा सबसे महत्वपूर्ण ढाँचों में से एक है और इसका उद्देश्य दुनिया के सभी बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा को अपरिहार्य बनाना है। सुदृढीकरण के लिए प्रशिक्षण को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। उन्हें गरीबों, आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से हतोत्साहित लोगों के दरवाजे तक पहुंचना चाहिये। अतः शिक्षा इसका सशक्त माध्यम है शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य को समर्थ बनाया जा सकता है ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तित हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजों ने एक ओर विश्व में कामगारों की जगह मशीनों को जगह देने की शुरुआत कर दी है तो दूसरी ओर साइंस तकनीकी और गणित के क्षेत्र में ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और मांग बढ़ती जा रही है जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी जैसे विविध विषयों में योग्यता रखते हो। अतः इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु एक सशक्त नीति की भी आवश्यकता है।

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अगस्त माह में इससे संबंधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी की गई। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 में बनाई गई थी और 1992 में संशोधित की गई थी। तब से कई बदलाव हुए हैं जो नीति में संशोधन की मांग करते हैं। एनईपी 2020-21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह चौत्तीस वर्षीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1986 की जगह लाई गई है। इसकी इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के मूलभूत स्तंभों पर निर्मित, यह नीति सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में बदलना है, जिसमें स्कूल और कॉलेज शिक्षा दोनों को अधिक समग्र, लचीला, बहु-विषयक, 21 वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल बनाया गया है और इसका उद्देश्य प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। आधुनिक भारत में नई शिक्षा नीति का विशिष्ट महत्व है। इनसे रचनात्मक और नवाचार को महत्व मिलेगा। शिक्षा नीति के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती विश्वविद्यालयों और

कॉलेजों में प्रोफेसरो की जवाबदेही और प्रदर्शन सुनिश्चित करने से संबंधित सूत्र को लागू करना भी है। आज, दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में, अपने साथियों और छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर शिक्षकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।

यह कहा जा सकता है कि NEP2020 सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है, लेकिन इसमें कई चुनौतियाँ भी हैं। उल्लेखनीय है कि इन चुनौतियों से निपटने का प्रयास पूर्व में भी किया जा चुका है, लेकिन उपलब्धियाँ सराहनीय नहीं रही हैं। इस संदर्भ में, कुछ सुझावों को यहां लागू करने की आवश्यकता है। इस नीति के तहत, शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार, नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं, विशेषज्ञों, अभिभावकों, समुदाय के सदस्यों को अपने स्तर पर काम करना चाहिए।

मूल शब्द - राष्ट्रीय शिक्षा नीति, चुनौतियाँ, संभावनाएं।

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020), जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। नई शिक्षा नीति 2020 ने पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, की जगह ले ली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य 2021 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है और यह नीति 2020 भारत को बदलने में सीधे प्रकार से योगदान प्रदान करती है और भारतीय लोकाचार में निहित शिक्षा प्रणाली को देखती है। इसका उद्देश्य धर्म, लिंग, जाति या पंथ के किसी भी भेदभाव के बिना, सभी को आगे बढ़ने और विकसित होने के लिए एक समान मंच प्रदान करना और सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके मौजूदा जीवंत ज्ञान समाज को बनाए रखना और उसकी देखभाल करना है। यह भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने की दिशा में भी एक कदम है।

इस नीति में यह परिकल्पना की गई है कि हमारे संस्थानों के समान पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र को, छात्रों में मौलिक कर्तव्यों के प्रति सम्मान की भावना पैदा करनी चाहिए और संवैधानिक मूल्यों, अपने देश और एक बदलती दुनिया के साथ एक संबंध पैदा करना चाहिए। इस नीति का दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच ज्ञान, कौशल, आत्मविश्वास, बुद्धि और कर्म के साथ न केवल विचार बल्कि मूल्यों और दृष्टिकोणों में भी विकास करना है, जो मानव अधिकारों, सतत विकास और जीवन का समर्थन करते हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

- (1) NEP 2020 के बारे में जानना।
- (2) NEP 2020 के लक्ष्यों एवं सिद्धान्तों के बारे में जानना।
- (3) NEP 2020 की संभावनाओं के बारे में जानना।
- (4) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियों के बारे में जानना।

शोध विधि

यह शोधपत्र द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से लिखा गया है। इस हेतु विभिन्न रिपोर्ट, समाचार पत्रों एवं पुस्तकों से तथ्यों का संकलन किया गया है।

NEP 2020 एक परिचय

नई शिक्षा नीति शिक्षार्थियों के एकीकृत विकास पर केंद्रित है।

यह 10+2 सिस्टम को 5+3+3+4 संरचना के साथ बदल देता है, जिसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की प्री-स्कूलिंग होती है, इस प्रकार बच्चों को पहले चरण में स्कूली शिक्षा का अनुभव होता है।

परीक्षाएं केवल 3, 5 और 8वीं कक्षा में आयोजित की जाएंगी, अन्य कक्षाओं का परिणाम नियमित मूल्यांकन के तौर पर लिए जाएंगे। बोर्ड परीक्षा को भी आसान बनाया जाएगा और एक वर्ष में दो बार आयोजित किया जाएगा ताकि प्रत्येक बच्चे को दो मौके मिलें।

नीति में पाठ्यक्रम से बाहर निकलने के अधिक लचीलेपन के साथ स्नातक कार्यक्रमों के लिए एक बहु-अनुशासनात्मक और एकीकृत दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है।

राज्य और केंद्र सरकार दोनों शिक्षा के लिए जनता द्वारा अधिक से अधिक सार्वजनिक निवेश की दिशा में एक साथ काम करेंगे, और जल्द से जल्द जीडीपी को 6% तक बढ़ाएंगे।

संभावनाएं

नई शिक्षा नीति सीखने के लिए पुस्तकों का बोझ बढ़ाने के बजाय व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ाने पर ज्यादा केंद्रित है।

एनईपी यानी नई शिक्षा निति सामान्य बातचीत, समूह चर्चा और तर्क द्वारा बच्चों के विकास और उनके सीखने की अनुमति देता है।

एनटीए राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालयों के लिए एक आम प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा।

छात्रों को पाठ्यक्रम के विषयों के साथ-साथ सीखने की इच्छा रखने वाले पाठ्यक्रम का चयन करने की भी स्वतंत्रता होगी, इस तरह से कौशल विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

सरकार एनआरएफ (नेशनल रिसर्च फाउंडेशन) की स्थापना करके विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर पर अनुसंधान और नवाचारों के नए तरीके स्थापित करेगी।

यह सीखने वाले की आत्म-क्षमता, संज्ञानात्मक कौशल पर जोर देता है। यह एक बच्चे को अपनी प्रतिभा विकसित करने में मदद करेगा यदि वे जन्मजात प्रतिभावान हैं तो।

पहले छात्रों के पास अध्ययन के लिए केवल एक ही विषय चुनने का विकल्प था, लेकिन अब अलग-अलग विषय चुन सकते हैं, उदाहरण के लिए – गणित के साथ-साथ कला और शिल्प का भी विकल्प चुन सकते हैं।

हर विषय पर समान रूप से व्यवहार करने पर जोर।

इस नीति का मुख्य उद्देश्य छात्रों के बीच नवीन विचारों के समावेश के साथ सहभागिता, महत्वपूर्ण सोच और तर्क करने की क्षमता को विकसित करना है।

स्नातक पाठ्यक्रमों में कई निकास विकल्प छात्रों को अनुभव से लाभान्वित करने और इस बीच कहीं काम करने से कौशल प्राप्त करने और फिर बाद में जारी रखने का अवसर प्रदान करेंगे।

नई शिक्षा नीति किसी भी विषय को सीखने के व्यावहारिक पहलू पर केंद्रित है, क्योंकि यह अवधारणा को समझने का एक बेहतर तरीका माना जाता है।

2040 तक सभी संस्थान और उच्च शिक्षण संस्थान बहु-विषयक बन जाएंगे।

NEP 2020 के तहत प्रमुख पहलें:

उभरते भारत के लिये PM स्कूल (SHRI): PM-SHRI योजना का उद्देश्य न्यायसंगत, समावेशी और मनोरंजक स्कूली वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है।

यह देश भर में 14500 से अधिक स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिये सितंबर 2022 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

पीएम-श्री पहल के तहत स्कूलों को अपग्रेड करने के लिये 630 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।

निपुण भारत: 'बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिये राष्ट्रीय पहल- निपुण' (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy- NIPUN) भारत मिशन का दृष्टिकोण मूलभूत साक्षरता तथा संख्यात्मकता के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने हेतु एक सक्षम वातावरण बनाना है ताकि प्रत्येक बच्चा वर्ष 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक पढ़ने, लिखने और संख्यात्मकता में वांछित सीखने की दक्षता हासिल कर सके।

पीएम ई-विद्या: इस पहल का उद्देश्य दीक्षा जैसे विभिन्न ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रदान करके और देश भर के छात्रों को ई-पुस्तकें तथा ई-सामग्री प्रदान कर ऑनलाइन शिक्षा एवं डिजिटल शिक्षण को बढ़ावा देना है।

NCF FS और जादुई पिटारा: 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों हेतु खेल-आधारित अध्ययन की शिक्षण सामग्री हेतु मूलभूत चरण के लिये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (National Curriculum Framework for Foundational Stag- NCF FS) और जादुई पिटारा शुरू की गई है।

निष्ठा: 'नेशनल इनीसिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलीस्टिक एडवांसमेंट' अर्थात् निष्ठा (National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement- NISHTHA) भारत में शिक्षकों और स्कूल प्रधानाचार्यों के लिये एक क्षमता-निर्माण कार्यक्रम है।

नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर (NDEAR): यह वास्तुशिल्प संबंधी ब्लूप्रिंट है, जो शिक्षा से संबंधित डिजिटल प्रौद्योगिकी-आधारित अनुप्रयोगों को सक्षम बनाने हेतु मार्गदर्शक सिद्धांतों का एक सेट तैयार करता है।

शैक्षणिक रूपरेखा: क्रेडिट हस्तांतरण और शैक्षणिक लचीलेपन की सुविधा के लिये राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF) तथा राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (NHEQF) की शुरुआत।

शिक्षा क्षेत्र में निवेश में वृद्धि: इस नीति के अनुसार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों को शिक्षा क्षेत्र के लिये सकल घरेलू उत्पाद का संयुक्त रूप से 6% आवंटित करना होगा।

NEP2020 की चुनौतियां

भाषा का कार्यान्वयन यानि क्षेत्रीय भाषाओं में जारी रखने के लिए 5वीं कक्षा तक पढ़ाना एक बड़ी समस्या हो सकती है। बच्चे को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा और इसलिए अंग्रेजी भाषा के प्रति कम दृष्टिकोण होगा, जो 5वीं कक्षा पूरा करने के बाद आवश्यक है।

बच्चों को संरचनात्मक तरीके से सीखने के अधीन किया गया है, जिससे उनके छोटे दिमाग पर बोझ बढ़ सकता है।

संस्थागत स्वायत्तता का अभाव है। कई संस्थानों को स्वायत्तता की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे अनुकूलन और नवाचार करने की उनकी क्षमता में बाधा आती है।

पैनल ने वर्तमान उच्च शिक्षा प्रणाली के अंदर अनुसंधान पर कम जोर दिया। जो की एक बहुत बड़ी चुनौती है।

यह कहा जा सकता है की नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा रटने वाले विषयों, समय सीमा को पूरा करने और अंक प्राप्त करने से कहीं अधिक है, लेकिन शिक्षा का वास्तविक अर्थ ज्ञान, कौशल, मूल्यों को प्राप्त करना और उस क्षेत्र में निरंतर कार्य करना और प्रगति करना है, जिसमें व्यक्ति अपनी रुचि खोज की करता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अगर नई शिक्षा नीति 2020 को सही तरीके से लागू किया जाए तो यह भारतीय शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। हालाँकि इसके कुछ उद्देश्यों में लक्ष्यों की स्पष्टता का अभाव है, लेकिन हम वास्तव में इसका न्याय तब तक नहीं कर सकते जब तक कि इसकी लिखित योजनाएँ क्रिया में न आ जाएँ। हम केवल सर्वोत्तम परिणामों की आशा कर सकते हैं, आखिरकार, यह छात्रों के समग्र विकास और प्रगति को ध्यान में रखते हुए लाई गयी है।

निष्कर्ष

वर्तमान शिक्षा प्रणाली वर्ष 1986 की मौजूदा शिक्षा नीति में किए गए परिवर्तनों का परिणाम है। इसे शिक्षार्थी और देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति बच्चों के समग्र विकास पर केंद्रित है। इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य है। इसमें अनेक संभावनाओं के साथ चुनौतियां भी है जिन्हे भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

सन्दर्भ सूची

NEP 2020: Implementation Challenges. Available on:
<https://www.educationworld.in/nep-2020-implementation-challenges/>

India Education Diary.

Highlights of New Education Policy 2020. available on:

<https://indiaeducationdiary.in/highlights-ofnew-education-policy-2020/> India Education Diary.com

[https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final English 0.pdf](https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf)

<https://innovate.mygov.in/wpcontent/uploads/2019/06/mygov>

[https://en.wikipedia.org/wiki/National Education Policy_2020](https://en.wikipedia.org/wiki/National_Education_Policy_2020)

Gupta, Stuti (2020). Role and Perspective Contribution of Technology in Education Sector with respect to National Education Policy 2020. In Gupta. Payal (Ed)

National Education Policy (2020) A paradigm shift in Indian Education Ishika Book Distribution, p183.

Kumar, K. (2005). Quality of Education at the Beginning of the 21st Century: Lessons from India. Indian Educational Review Draft National Education Policy 2019.

Manoj, Ambika (2021): National Education Policy-2020: Issues and Challenges in implementation. University news Vol.59, no-5, April 12-18. p.146.

NEP 2020: Implementation challenges, Ministry of Education. [Indiatoday.in/education-today/feature-philia/story/a-reality-check-on-nep-2020-major-challenges-in-implementation-1711197-2020-08-14](https://indiatoday.in/education-today/feature-philia/story/a-reality-check-on-nep-2020-major-challenges-in-implementation-1711197-2020-08-14).

